Recommendations	Status
6. The Committee noted that another area which needs proper attention was the augmentation of repair facilities. The Committee urged that the wide gap of 1600 dry dock days for repairing facilities be made up at the earliest.	The Ministry fully concurred that the repair facilities require substantial and urgent augmentation. A study was carried out by Asian Development Bank under its Technical Aid Programme. The report has been received from the ADB and is under process in the government. Meanwhile ship repair capacity has been augmented by setting up a modern ship repair complex comprising two floating docks at Madras Port.
7. The Committee noted that the 55% of the total tonnage is already under government control. The Committee was of the view that the Govt. keep the issue relating to nationalisation of shipping industry open and review at appropriate time.	The present policy of the Government is against Nationalisation of shipping industry.
8. The Committee also recommended that the suggestion relating to the reintroduction system of cargo pooling which was discontinued in 1983 is worth considering. This may be examined and decision taken. The Committee also recommended that the government may ensure shiping industry may develop in a planned manner so that employment opportunities for the seamen are enhanced.	The Government considered the recommendation of the Committee and in view of the various reasons, it was felt that it would not be feasible to reintroduce pooling system. The suggestion of the Committee that shipping industry may develop in a planned manner is kept in veiw while formulating policies relating to development of shipping industry.

It may be observed that most of the recommendations made by the Committee of Petitions are either in the form of observation or general in nature for the development of shipping, shipbuilding and ports sector. These have been kept in view while formulating plan and policies for the above mentioned sectors.

आठवीं योजना के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

1209. **श्री शिवचरण सिंह:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में कितने किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किये जाने की संभावना है;

(ग) उक्त प्रयोजन के लिए धनराशि का आवंटन करने का क्या मानदंड है;

(घ) इस तथ्य के बावजूद कि राजस्थान का विशाल भू-भाग है, राज्य में भूमि क्षेत्र के अनुपात में राष्ट्रीय राजमार्ग कम होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या राज्यों को राजनीतिक आधार पर धनराशि आवंटित की जाती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) एक विवरण संलग्न है। (**नीचे देखिए**)

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उपलब्ध कराए गए सीमित आबंटन के कारण

इस समय राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में कोई नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना कठिन है।

(ग) आठवीं योजना के दौरान सीमित संसाधनों के कारण मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा किसी क्षेत्र/प्रदेश/आबादी अथवा राज्य के स्तर के आधार पर नहीं अपितु पूरे देश की आवश्यकता को ध्यान में रखकर की जाती है। तथापि, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है।

(ङ) जी, नहीं। निधियों का आबंटन, यातायात संबंधी आवश्यकता अनुमोदित कार्यों तथा संसाधनों की सकल उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

विवरण

गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा

क्रम सं॰	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43
2.	अरूणाचल प्रदेश	52,52ए
3.	आसाम	31, 31-बी, 31-सी, 36, 37, 37-ए,38, 39, 44, 51, 52, 52-ए, 53, 54
4.	बिहार	2, 6, 23, 28, 28-ए, 30, 31, 32, 33
5.	चंडीगढ़	21
6.	दिल्ली	1, 2, 8, 10, 24
7.	गोवा	4-ए, 17, 17-ए
8.	गुजरात	8, 8-ए, 8-बी, 8-सी, 14, 15,एन॰ई-1
9.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 22
10.	हिमाचल प्रदेश	1-ए, 20, 21, 22
11.	जम्मू और कश्मीर	1-ए, 1-बी
12.	कर्नाटक	4, 4-ए, 7, 9, 13, 17, 48
13.	केरल	17, 47, 47-ए, 49
14.	मध्य प्रदेश	3, 6, 7, 12, 16, 25, 26, 27, 43
15.	महाराष्ट्र	3, 4, 4-ई, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50
16.	मणिपुर	39,53
17.	मेघालय	40, 44, 51
18.	मिजोरम	54, 54-ए, 54-बी
19.	नागालैंड	36, 39
20.	उड़ीसा	5, 5-ए, 6, 23, 42, 43
21.	पंजाब	1, 1-ए, 10, 15, 20, 21, 22
22.	राजस्थान	3, 8, 11, 1-ए, 12, 14, 15
23.	सिक्किम	31-ए
24.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7-ए, 45, 45-ए, 49
25.	त्रिपुरा	44
26.	उत्तर प्रदेश	2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 56
27.	पश्चिम बंगाल	2, 6, 31, 31-ए, 31-सी, 32, 34, 35, 41, 55
28.	पांडिचेरी	45-ए

12 NOON

[THE DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair]*

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. Administration Report (1991-92) of the Calcutta Dock Labour Board and related Papers.
II. Report (1991-92) of the Bombay Dock Labour Board and related Papers.